समाज के कमजोर वर्गों के लिये आवास सुविधायें

*286. **चौधरी हरमोहन सिंह:**
श्री आस मोहम्मद:

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार समाज के कमजोर वर्गों को आवास सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु क्या-क्या प्रयास कर रही है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में कौन-कौन सी परियोजनायें शुरू की गई है; और

(ग) इस संबंध में अब तक कितने प्रतिशत प्रगति हुई है?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल): (क) और (ख) राष्ट्रीय आवास नीति में समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की मकानों की जरूरत पर विशेष बल दिया गया है। नीति का मुख्य लक्ष्य सभी लोगों विशेषकर बेघरों, तंग आवास वाले लोगों और कमजोर वर्गों को सहायता करना है, ताकि वे अपने लिए सस्ते मकान प्राप्त कर सकें।

आवास राज्य का विषय होने के कारण आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की योजनाओं सहित सभी सामाजिक आवास योजनाएं बनाने और कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकारें उत्तरदायी हैं। केन्द्र सरकार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में समाज के कमजोर वर्गों के लिए विभिन्न केन्द्रीय तथा केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं चला कर राज्य सरकारों के प्रयासों को बल प्रदान करती है।

केन्द्र सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के आवास के लिए कोई नयी योजना प्रारम्भ नहीं की गयी है। तथापि, नेहरू रोजगार योजना और शहरी पटरीवालों के लिए रैन बसेरे और सफाई सुविधा के तहत् आश्रय सुधार की केन्द्रीय सैक्टर की योजनाएं वर्ष 1988-89 से चलाई जा रही हैं। ग्रामीण आवास के बारे में निर्धन अनुसूचित जाति / अनुसूजनजाति परिवारों की मुक्त बंधुआ मजदूरों के लिए इन्दिरा आवास योजना नामक शत-प्रतिशत इमदाद योजना, छठी पंचवर्षीय योजना से ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों में चलायी जा रही है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन शुरू करने वाले परिवारों के लिए 350 करोड़ रु. की एक नई केन्द्र प्रवर्तित योजना भी शुरू की है।

(ग) आर्थिक रूप से कमजोर आवास योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारों द्वारा की गयी प्रगति का निरीक्षण केन्द्र सरकार द्वारा 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अंग के रूप में किया जाता है। इस बारे में राज्य सरकारों द्वारा सूचित उपलब्धियों का विवरण इस प्रकार है:

रिहायशी मकान (लाखों में)

योजनावधि	लक्ष्य	लब्धि	लब्धि प्रतिशत
छठी योजना	16.20	8.27	51.05
सातवीं योजना	7.75	7.14	92.13
वार्षिक योजना (1990-91)	0.72	0.74	102.78
वार्षिक योजना (1991-92)	1.11	0.97	87.39
आठवीं योजना (1992-93)	1.15	0.99	89.00
(1993-94)	0.83	1.22	147.00
(1994-95)	1.03	–	–

इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत शुरू से लेकर मार्च, 1994 तक 6.42 लाख मकान बनाए गए हैं। 30 जून, 1994 तक हुडको ने ई॰ डब्ल्यू॰ एस॰ परिवारों के लिए 35,35,034 रिहायशी ईकाइयों के निर्माण और 2,13,809 विकसित प्लाटों के लिए ऋण मंजूर किया है।

हथनीकुण्ड बांध का निर्माण

*287. **श्री सोमपाल:**
डा॰ नौनिहाल सिंह:

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) यमुना नदी पर हथनीकुण्ड बांध के निर्माण की दिशा में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या केन्द्रीय जल आयोग ने इस संबंध में तकनीकी अध्ययन एवं जांच पूरी कर ली है;

(ग) यदि हां, तो इस बांध का निर्माण कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है और इससे विभिन्न राज्यों, विशेषकर हरियाणा और उत्तर प्रदेश को क्या-क्या लाभ प्राप्त होने की संभावना है; और

(घ) क्या विद्युत का उत्पादन भी इस परियोजना का एक लक्ष्य है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) हरियाणा सरकार ने हथनी-कुण्ड बराज के प्रारंभिक कार्यों पर 1865.11 लाख रुपए व्यय किए हैं;

(ख) जी नहीं, संशोधित परियोजना रिपोर्ट जून, 1994 में प्राप्त हुई है;

(ग) परियोजना रिपोर्ट के अनुसार, हथनीकुंड बराज के जून, 1997 तक पूरा किए जाने का कार्यक्रम है, काफी पुराने ताजेवाला बराज, जिसकी सुरक्षा के प्रति आशंका है, के स्थान पर इस बराज की परिकल्पना की गई है;

(घ) जी नहीं, हथनीकुंड बराज में विद्युत उत्पादन की परिकल्पना नहीं की गई है।

Schemes for Construction of Houses for Low Income Group

*288. SHRI AAS MOHAMMAD:
SHRI KANAKSINH MOHANSINH MANGROLA:

Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) the schemes drawn up for the construction of houses for low income group;

(b) the number of persons likely to be benefitted by theses schemes;

(c) whether Government are aware that the soaring prices of land in urban and semi-urban areas are much beyond the reach of the common man and if so, the steps Government propose to take to overcome this problem and to provide shelter to these people; and

(d) the funds earmarked for housing sector during Eighth Five Year Plan period?

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT (SHRIMATI SHEILA KAUL): (a) and (b) Housing being a State subject, State Governments are responsible for the formulation and implementation of housing schemes for different income groups in accordance with their priorities and available resources. The progress of Low Income Group Housing Schemes in the States is monitored by the Central Government under the 20-Point Programme. As per informaiton made available by the State Governments in this connection, the progress achieved under LIG housing scheme since the 7th Five year Plan is as follows:

(Dewelling Units in lacs)

Plan Period	Target	Achieve-ment	per-centage
7th Plan	1.30	1.67	102.14
Annual Plan 1990-91	0.50	0.52	104.00
Annual Plan 1991-92	0.52	0.59	113.46
8th Plan1992-93	0.52	0.51	95.00
8th Plan1993-94	0.45	0.59	132.00
8th Plan1994-95	0.51	—	—

(c) Due to general inflationary trend and all-round cost escalation, the cost of housing, including cost of land in urban areas, has increased and the affordability of low income group households has accordingly been adversely affected. With a view to helping low income group households, housing finance is made available by HUDCO at subsidised rates of interest. Moreover the following steps have been taken to bring down the cost of housing units to make them affordable to low income category households:

(i) The State Governments have been addressed for effecting saving in construction cost of houses being put up by State housing agencies by incorporating cost effective alternate building materials and technologies.

(ii) To promote cost effective building materials and technologies on a decentralised basis, a National Network of Building Centres has been established.

(iii) The Building Materials and Technology Promotion Council (BMTPC) has been set up and this body and the Bureau of Indian Standards (BIS) have jointly formulated specifications on cost-effective building materials and technogues which have been incorporated in the schedules of CPWD. The State Government have been advised to incorporate these specifications in their PWD schedules.

(iv) To bring down the cost of new construction materials, including those manufactured from industrial wastes like flyash, phospohgypusm, etc. customs and excise duty concessions have been provided by the Government.